डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 अक्टूबर, 2023, डिस्पेच दिनांक 1 अक्टूबर, 2023

| वर्ष 67 | अंक 09 | भोपाल | 1 अक्टूबर, 2023 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश में अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन कर कोऑपरेटिव आंदोलन में एक नई जान डालकर गति दी है

- भारत में आज़ादी के बाद सहकारिता ने सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट मॉडल्स के बीच का एक मॉडल देने का बहुत अच्छा प्रयास किया, जिसमें कोऑपरेशन और सबके हित की कल्पना लेकर आगे बढ़ने का विचार था
- सहकारिता मॉडल हमारे देश के लिए बहुत उपयुक्त है क्योंकि हमें आर्थिक विकास के साथ-साथ रोजगार, mass production और production by masses भी चाहिए, mass production से देश के अर्थतंत्र को गति मिलेगी और production by masses से देश के हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा
- देश के अर्थतंत्र से जुड़ी संस्थाओं के साथ सहकारिता क्षेत्र का बेहतरीन संयोजन ही भारत को आगे बढ़ा सकता है
- प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से 2023 तक देश के उन 60 करोड़ लोगों, जो देश के अर्थतंत्र का हिस्सा ही नहीं थे, को बैंक अकाउंट, घर, पीने का पानी, बिजली, गैस कनेक्शन और शौचालय दिया, जिससे इन 60 करोड़ लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ
- इन 60 करोड़ लोगों को देश के विकास में योगदान देने, Women-led Development को आगे बढ़ाने, ग्रामीण विकास को महत्व देकर शहरों की ओर पलायन रोकने और हर व्यक्ति को देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का सहकारिता के सिवा कोई और मॉडल नहीं हो सकता
- मोदी जी ने निर्णय लिया है कि आने वाले 5 सालों में 3 लाख नए पैक्स बनाएंगे और हर पंचायत में एक पैक्स होगा और यह पैक्स मल्टीडाइमेंशनल होंगे
- मोदी सरकार ने 20 प्रकार की नई गतिविधियों को पैक्स के साथ जोड़कर इन्हें वायबल बना दिया है, सरकार ने मॉडल बायलॉज बनाकर सभी राज्यों को भेजे हैं और देश के 23 राज्यों ने इन मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया है
- मोदी सरकार आने वाले दिनों में सहकारिता क्षेत्र में कई नए कदम उठाने जा रही है, जिनसे कोऑपरेटिव का भविष्य और उज्जवल होने जा रहा है
- मुंबई विश्वविद्यालय ने लक्ष्मणराव इनामदार जी के नाम से एक पीठ स्थापित कर उनके विचारों को विद्यार्थियों के माध्यम से युगों-युगों तक पहुँचाने की नींव रखी है

दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में मुंबई विश्वविद्यालय और सहकार भारती द्वारा आयोजित माननीय लक्ष्मणराव इनामदार स्मृति व्याख्यान में संबोधन दिया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस और मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि लक्ष्मणराव जी महाराष्ट्र में जन्मे और गुजरात को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया और पूरा जीवन गुजरात के युवाओं के प्रेरणास्त्रोत बने। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों के बड़े नेतों और कार्यकर्ताओं का सृजन लक्ष्मणराव इनामदार जी को मिला। उन्होंने कहा कि इनामदार जी द्वारा गढ़े और तैयार किए हुए अनेक कार्यकर्ताओं ने उनके द्वारा दिए संस्कारों के आधार पर गुजरात के सार्वजनिक जीवन को महिमामंडित करने का काम किया है। वकील साहब अपने साथ काम करने वाले कार्यकर्ता को संस्कारों से सिंचित कर उन्हें अमूल्य बना देते थे और एक लोहे जैसा कार्यकर्ता उनके स्पर्श में आते ही सोने जैसा हो जाता था। श्री शाह ने कहा कि गुजरात का सार्वजनिक जीवन आज शुचितायुक्त है, इसमें इनामदार जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि मुंबई विश्वविद्यालय ने लक्ष्मणराव इनामदार जी के नाम से एक पीठ स्थापित कर उनके विचारों को विद्यार्थियों के माध्यम से युगों-युगों तक पहुँचाने की नींव रखी है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि देशभर के सहकारिता क्षेत्र के प्रमुख नेताओं में आज लक्ष्मणराव जी को सभी लोग आदरपूर्वक याद करते हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र के इन सभी नेताओं में से अकेले इनामदार जी एक ऐसे नेता थे जो किसी भी सहकारी समिति के ना तो सदस्य थे, ना ही पदाधिकारी थे लेकिन फिर भी सहकारिता क्षेत्र में उनका योगदान बहुत बड़ा था। श्री शाह ने कहा कि लक्ष्मणराव इनामदार जी में सहकार का तत्व, सिद्धांत और सहकारिता के अंदर व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए बौद्धिकता थी और इसी से उन्होंने इतने वर्षों तक 'सहकार भारती' का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये इनामदार जी के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज सहकार भारती एक अलग आयाम के साथ यहां खड़ी दिखाई देती है। श्री अमित शाह ने कहा कि कोई व्यक्ति निस्वार्थ जीवन कैसे जी सकता है और जीता है और इससे किस प्रकार की सुगंध फैलती है, इसके बारे में जानने के लिए गुजरात के सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों से इनामदार जी के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनामदार जी ने अनेक लोगों को जीवन जीने का उद्देश्य दिया, उसे प्राप्त करने का हौसला भी दिया और उद्देश्य प्राप्ति के रास्ते से कभी ना भटकने का साहस भी दिया।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत में सहकारिता आंदोलन 1904 से आया और देखते-देखते महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य भारत, तमिलनाडु और बंगाल में सहकारिता आंदोलन फैलने लगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद सहकारिता ने सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट मॉडल्स के बीच का एक मॉडल देने का बहुत अच्छा प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अन्य दो मॉडल्स में स्टेट और मार्केट की कल्पना थी, लेकिन सहकारिता मॉडल में कोऑपरेशन और सबके हित की कल्पना लेकर आगे बढ़ने का विचार था। श्री शाह ने कहा कि शुरुआती दिनों में कई लोगों ने सहकारिता के क्षेत्र को एक नई दिशा और संस्कार देने का काम किया।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

MP STATE COOPERATIVE UNION LTD.
E-8/77, SHAHPURA, TRILANGA ROAD BHOPAL - 462039
Email : rajyasanghbpl@yahoo.co.in
Website:www.mpscu.in, Tel.: 0755-2926160

EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR EMPANELMENT OF MANPOWER OUTSOURCING AGENCY

Expression of Interest (EOI) is invited for empanelment of Manpower Out Sourcing Agency.

The detailed terms and conditions of the EOI are given on our website www.mpscu.in. Interested agencies may download EOI document from website.

The interested agencies may apply as per the directives mentioned in the EOI document on or before 10.10.2023 by 5 P.M. in the office of under signed. The Managing Director reserves the right to cancel this EOI without assigning any reason.

Attached :

1. Terms
2. Expression of Interest (EOI)
3. Evaluation Form

Managing Director

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने पीएम-किसान योजना के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया

यह केंद्र सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजना के साथ एकीकृत पहला AI (एआई) चैटबॉट है

AI चैटबॉट पीएम-किसान योजना की दक्षता और पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है

AI चैटबॉट किसानों को उनके प्रश्नों का त्वरित, स्पष्ट और सटीक उत्तर भी प्रदान करेगा

इस पहल के माध्यम से, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का लक्ष्य देश भर के किसानों को निर्बाध सहायता और समर्थन प्रदान करना है

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लिए AI (एआई) चैटबॉट (पीएम किसान मित्र) लॉन्च किया। एआई चैटबॉट का लॉन्च पीएम-किसान योजना की दक्षता और पहुंच बढ़ाने और किसानों को उनके प्रश्नों का त्वरित, स्पष्ट और सटीक उत्तर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

श्री कैलाश चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि क्षेत्र को तकनीक के साथ जोड़ने के लिए उठाया गया यह बड़ा कदम किसानों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। उन्होंने कहा कि आज कृषि मंत्रालय ने विभिन्न भाषाओं में AI (एआई) चैटबॉट के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर मोबाइल के माध्यम से करने की पहल कर उनकी शिकायतों का निपटान करने का एक महत्वपूर्ण काम किया है। कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुड गवर्नेंस के तहत तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का आह्वान किया है और आज की गई यह पहल उसमें मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि आज कृषि में तकनीक के इस्तेमाल का ही प्रभाव है कि किसान ड्रोन के माध्यम से खेती कर रहा है जिसके चलते युवा भी कृषि की ओर आकर्षित हो रहा है। इसी के चलते देश में कृषि के क्षेत्र में नए-नए स्टार्ट-अप शुरु हो रहे हैं।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने राज्य के अधिकारियों से अपील की कि वे किसानों को AI (एआई) चैटबॉट के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें व उचित निगरानी रखें और इसके प्रयोग के प्रारंभिक दौर में आने वाली समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान करें। उन्होंने इस पहल को मौसम की जानकारी, फसल नुकसान व मृदा की स्थिति की जानकारी देने, बैंक पेमेंट आदि से जोड़ने की बात पर बल दिया। राज्य मंत्री ने बहुत कम समय में तकनीक को शामिल करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों की सराहना की और कहा कि इससे केंद्र और राज्यों के कृषि अधिकारियों के ऊपर काम का बोझ कम हो जाएगा।

इस वर्चुअल लॉन्च कार्यक्रम के दौरान, भारत सरकार और राज्य सरकार के गणमान्य व्यक्ति कृषि क्षेत्र में इस उल्लेखनीय उपलब्धि का समारोह मनाने के लिए एकत्र हुए। पीएम किसान योजना के लिए एआई चैटबॉट का सफल लॉन्च किसानों के कल्याण के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नति का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

कृषि मंत्रालय के सचिव श्री मनोज आहूजा ने कहा कि इस पहल को अगले कुछ महीनों में कृषि मंत्रालय की सभी बड़ी योजनाओं में लागू किया जाएगा। कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, डॉ. प्रमोद मेहरदा ने चैटबॉट की विशेषताओं और किसानों के लिए इसके लाभों एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

यह केंद्र सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजना के साथ एकीकृत पहला AI (एआई) चैटबॉट है। AI (एआई) चैटबॉट माध्यम से देश भर के किसानों को निर्बाध सहायता और समर्थन प्रदान की जाएगी। योजना की जानकारी तक पहुंचने और शिकायतों को हल करने में किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए, कृषि और किसान कल्याण विभाग ने पीएम किसान हेतु एआई चैटबॉट पेश करने के लिए एक प्रगतिशील कदम उठाया। इस चैटबॉट को ईकेस्टेप(EKstep) फाउंडेशन और भाषिनी(Bhashini) के सहयोग से विकसित और बेहतर बनाया जा रहा है। एआई चैटबॉट लाभार्थियों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें योजना से संबंधित उनके प्रश्नों

का समय पर और सटीक उत्तर प्रदान करता है। पीएम-किसान शिकायत प्रबंधन प्रणाली में एआई चैटबॉट की शुरुआत का उद्देश्य किसानों को उपयोगकर्ता-अनुकूल और सुलभ प्लेटफॉर्म के साथ सशक्त बनाना है। विकास के अपने पहले चरण में, एआई चैटबॉट किसानों को उनके आवेदन की स्थिति, भुगतान विवरण, अपात्रता की स्थिति और अन्य योजना-संबंधित अपडेट की जानकारी प्राप्त करने में सहायता करेगा।

पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से सुलभ एआई चैटबॉट को भाषिनी के साथ एकीकृत किया गया है, जो पीएम किसान लाभार्थियों की भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को पूरा करते हुए बहुभाषी समर्थन प्रदान करता है। उन्नत प्रौद्योगिकी के इस एकीकरण से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि किसानों को सूचित निर्णय लेने में भी सशक्त बनाया जाएगा। वर्तमान में चैटबॉट अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, उड़िया और तमिल में उपलब्ध है। कुछ ही समय में यह देश की सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध होगा।

बैकग्राउण्ड -

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) भारत में भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से पात्र किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये का वार्षिक वित्तीय लाभ प्रदान करती है। इसकी स्थापना के बाद से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.61 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं, यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है।

पीएम-किसान योजना ने देश भर में खेती योग्य भूमि वाले भूमिधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ने महिला लाभार्थियों सहित लाखों किसानों को समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित की है, जो उनके सामाजिक-आर्थिक कल्याण में योगदान दे रही है। कोविड महामारी के दौरान, लाभार्थियों को 1.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए गए, जिससे किसानों और उनके परिवारों को कठिन समय में बड़ी राहत मिली।

भारत सरकार ने फेस ऑथेंटिकेशन-आधारित ई-केवाईसी की सुविधा वाला एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया है। यह ऐप पहला मोबाइल ऐप है जो सरकार की किसी भी लाभ योजना में फेस ऑथेंटिकेशन-आधारित ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग करता है। इस मोबाइल ऐप का उपयोग करना बहुत आसान है और यह गूगल प्ले स्टोर पर सरलता से डाउनलोड किया जा सकता है। यह ऐप आधुनिक प्रौद्योगिकी का अद्भुत उदाहरण है, जिसके माध्यम से अब किसान घर बैठे देश के दूर-दराज के इलाकों में भी बिना किसी ओटीपी या फिंगरप्रिंट के सिर्फ अपना चेहरा स्कैन करके अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वे अपने पड़ोस के 100 अन्य किसानों को भी उनके दरवाजे पर ई-केवाईसी पूरा करने में सहायता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए किसानों की ई-केवाईसी पूरी करने की सुविधा भी बढ़ा दी है, जिससे प्रत्येक अधिकारी को 500 किसानों के लिए ई-केवाईसी करने की अनुमति मिल गई है।

एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

जबलपुर, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा एकलव्य मछुआ सहकारी समिति मर्यादित दीधी जिला कटनी (म.प्र.) में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक पीयूष राय द्वारा किया गया। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष श्री राम किशोर केवट, सदस्यो मे श्री रमेश केवट, श्री मिठाई लाल कोल तथा समिति के अन्य सदस्यो ने प्रशिक्षण मे भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षक पीयूष राय ने प्रशिक्षार्थियो को सहकारी संस्थाओ की कार्यप्रणाली उनके लाभ तथा नए क्षेत्रो मे समितियो के गठन के संबंध में चर्चा की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में समिति के सदस्यों ने बडी संख्या में उपस्थित होकर प्रशिक्षण लिया।

दुर्गा मछुआ सहकारी समिति में प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन

जबलपुर, सहकारी प्रशिक्षण केंन्द्र जबलपुर द्वारा दुर्गा मछुआ सहकारी समिति मर्यादित सिजहरा जिला कटनी (म.प्र.) में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक पीयूष राय द्वारा किया गया। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष श्री कालू राम बर्मन, उपाध्यक्ष श्री माखन लाल, समिति के सदस्यो मे श्री कैलाश, श्री चंदा, श्री सीता राम तथा समिति के अन्य सदस्यो ने प्रशिक्षण मे भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक पीयूष राय ने प्रशिक्षार्थियो को सहकारी समिति के लाभ तथा उनके संचालन के संबंध मे चर्चा की। कार्यक्रम के अन्त में श्री माखन लाल जी ने आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लांच की

"वोकल फॉर लोकल" के प्रति समर्पण पूरे देश की जिम्मेदारी है - प्रधानमंत्री

विश्वकर्मा समाज में हमेशा महत्वपूर्ण बने रहेंगे, यह योजना उन्हें आधुनिक युग में ले जाने का एक प्रयास - प्रधानमंत्री

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में इस अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में शामिल हुए

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना देश के कारीगरों-शिल्पकारों के जीवन स्तर में बदलाव लाने में सफल होगी - श्री तोमर

मध्यप्रदेश की ग्रोथ रेट देश में सर्वाधिक है, अगले महीने राज्य में ग्लोबल स्किल पार्क भी बनकर तैयार हो जाएगा - श्री चौहान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर की गई अपनी घोषणानुसार आज विश्वकर्मा जयंती पर नई दिल्ली में विश्वकर्मा योजना लांच की। इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित हुए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (यशोभूमि) राष्ट्र को समर्पित की। विश्वकर्मा जयंती समारोह में अपने संबोधन उन्होंने कहा कि लाखों कारीगरों-परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना आशा की किरण बनकर आ रही है। उन्होंने देश के रोजमर्रा के जीवन में विश्वकर्माओं के योगदान व महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी में चाहे कितनी भी प्रगति क्यों न हो जाए, विश्वकर्मा समाज में हमेशा महत्वपूर्ण बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि विश्वकर्माओं को मान्यता दी जाए और उनका समर्थन किया जाए। सरकार विश्वकर्माओं का सम्मान, क्षमता व समृद्धि बढ़ाने के लिए भागीदार के रूप में आगे आई है। उन्होंने कहा कि दुनिया में बड़ी कंपनियां अपना काम छोटे उद्यमों को सौंप देती हैं। आउटसोर्स का यह काम हमारे विश्वकर्मा मित्रों को मिलें, वे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनें, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। योजना विश्वकर्मा मित्रों को आधुनिक युग में ले जाने का एक प्रयास है। बदलते समय में, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी व उपकरण विश्वकर्मा मित्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रशिक्षण में 500 रुपये प्रतिदिन भत्ता दिया जाएगा, आधुनिक टूलकिट के लिए 15 हजार रुपये का वाउचर दिया जाएगा। उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग में सरकार मदद करेगी। विश्वकर्मा मित्रों को बिना गारंटी बहुत कम ब्याज पर 3 लाख रु. तक ऋण मिलेगा। केंद्र वंचितों के विकास को प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा, "मोदी उन लोगों के लिए खड़े हैं, जिनकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। वह यहां सेवा करने, सम्मान का जीवन देने व यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि सेवाओं का वितरण बिना किसी असफलता के हो। यह मोदी की गारंटी है।" उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल के प्रति समर्पण पूरे देश की जिम्मेदारी है। पहले हमें लोकल के लिए वोकल बनना होगा और फिर लोकल को ग्लोबल बनाना होगा।

भोपाल में केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना देश के कारीगरों-शिल्पकारों के जीवन स्तर में बदलाव लाने में सफल होगी। श्री तोमर ने विश्वकर्मा जयंती व प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिन पर बधाई देते हुए कहा कि आजादी के बाद अनेक प्रधानमंत्रियों ने देश का नेतृत्व किया, जिन्होंने अपने-अपने समय में देश को आगे बढ़ाने में कुछ न कुछ योगदान किया ही है, लेकिन श्री मोदी का व्यक्तित्व सबसे अलग हटकर है, जहां एक ओर देश के गांव,गरीब,किसान,महिला,दलित,नौजवान की प्रगति के बारे में श्री मोदी विचार करते हैं, वहीं वैश्विक जगत में भारत की साख मजबूत हो, इस मामले में भी वे कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। चाहे चंद्रयान का मामला हो या आदित्य एल-1 अथवा भारत की अध्यक्षता में जी20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर कीर्तिमान स्थापित करने का विषय हो, ये सब इस ओर दृष्टिपात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता

भारत को आगे ले जाने वाली है। हमारे देश में बड़ी आबादी है, जिनमें नौजवान भी काफी है, तो स्वाभाविक रूप से इनके लिए रोजगार की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सालभर में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था और हर माह रोजगार मेले कर नियुक्ति-पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इसी तरह, मध्यप्रदेश में भी युवाओं को नौकरियां दी जा रही है, लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरियों से ही काम नहीं चलेगा, इसीलिए पीएम गति शक्ति, स्वनिधि, मुद्रा, ग्रामीण विकास आदि की योजनाओं से भी गांवों-शहरों के कुशल लोगों को स्वरोजगार मिल रहा है। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर 5 साल में 13 हजार करोड़ रुपये खर्च कर गुरू-शिष्य परंपरा या हाथों व औजारों से काम करने वाले कारीगरों-शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार-आधारित पेशे को मजबूत करते हुए बढ़ावा दिया जाएगा, जो केंद्र का अत्यंत सराहनीय कदम है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वोकल फॉर लोकल जैसे मंत्र व कई योजनाओं के जरिये से पीएम श्री मोदी ने भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है और उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। देश ने स्वास्थ्य-शिक्षा सहित हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की, उपलब्धियां हासिल की हैं, देश की सुरक्षा के लिए भी कड़ी कार्रवाई की गई है। श्री मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर के निर्माण जैसे सराहनीय कदम उठाए गए हैं। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश आज तेजी से तरक्की कर रहा है, जहां बिजली-पानी जैसी समस्याओं को दूर किया गया है, वहीं मध्यप्रदेश की ग्रोथ रेट आज देश में सबसे ज्यादा 16.9 प्रतिशत के आसपास है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री विश्वकर्मा सृष्टि के सर्वोच्च वास्तुकार है, वहीं सभी कारीगर व शिल्पकार हमारे लिए आधुनिक विश्वकर्मा है, जिनके बिना आज ये सृष्टि चल नहीं सकती। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से देश के कौशल तंत्र को राष्ट्र की जरूरतों के अनुसार ढालने का काम किया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाकर सुविधाओं से हमारे कारीगर अपनी स्किल को और बढ़ा पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को भी अपना हुनर सिखा पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले महीने के पहले सप्ताह में मध्यप्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क बनकर तैयार हो जाएगा।

भोपाल के समारोह में आईटीआई का दीक्षांत कार्यक्रम भी संपन्न हुआ और विद्यार्थियों को श्री तोमर व श्री चौहान ने सम्मानित किया। यहां मध्यप्रदेश के मंत्री श्री ओमप्रकाश सकलेचा व श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, क्षेत्रीय विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि व विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। भोपाल के कार्यक्रम का समन्वय राज्य शासन के साथ ही एमएसएमई तथा एनएचएआई द्वारा किया गया।

इस योजना में 18 व्यवसायों जैसे (i) बढ़ई; (ii) नाव निर्माता; (iii) हथियार निर्माता; (iv) लोहार; (v) हथौड़ा और टूल किट निर्माता; (vi) ताला बनाने वाला; (vii) सोनार; (viii) कुम्हार; (ix) मूर्तिकार (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला; (x) मोची/जूता कारीगर; (xi) राजमिस्त्री; (xii) टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉयर बुनकर; (xiii) गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक); (xiv) नाई; (xv) माला बनाने वाला; (xvi) धोबी; (xvii) दर्जी; और (xviii) मछली पकड़ने का जाल निर्माण में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है।

इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करने की व्यवस्था की गई है:

(i) पहचान: पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों की पहचान।

(ii) कौशल उन्नयन: 500 रुपये प्रति दिन के वजीफे के साथ 5-7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण।

(iii) टूलकिट प्रोत्साहन: बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में ई-वाउचर के रूप में 15,000 रु. रुपये तक का टूलकिट प्रोत्साहन।

(iv) कर्ज सहायता: बिना कुछ गिरवी रखे 'उद्यम विकास ऋण' के रूप में तीन लाख रुपए तक का ऋण एक लाख और दो लाख रुपए के दो किश्तों में क्रमशः 18 महीने और 30 महीने की अवधि के लिए 5 प्रतिशत निर्धारित रियायती ब्याज दर पर भारत सरकार द्वारा 8 प्रतिशत की सीमा तक छूट के साथ प्रदान किया जाएगा। जिन लाभार्थियों ने बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, वे एक लाख रुपये तक की ऋण सहायता की पहली किश्त का लाभ उठाने के पात्र होंगे। दूसरी ऋण किश्त उन लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने पहली किश्त का लाभ उठाया है और एक मानक ऋण खाता बनाए रखा है और अपने व्यवसाय में डिजिटल लेनदेन को अपनाया है या उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

(v) डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन: प्रत्येक डिजिटल भुगतान या रसीद के लिए प्रति डिजिटल लेनदेन एक रुपये की राशि के हिसाब से अधिकतम 100 लेनदेन मासिक तक लाभार्थी के खाते में जमा किया जाएगा।

(vi) विपणन सहायता: मूल्य श्रृंखला से जुड़ाव में सुधार के लिए कारीगरों और शिल्पकारों को गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, जीईएम जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर मौजूदगी, विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों के रूप में विपणन सहायता प्रदान की जाएगी।

बिहार राज्य के सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के प्रशिक्षण माड्यूल हेतु बैठक आयोजित

भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल के द्वारा कार्यालय निबंधक सहयोग समिति पटना बिहार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में कोर्स माड्यूल एवं प्रशिक्षण संबंधित अन्य समस्त व्यवस्थाओं हेतू दिनांक 26 सितंबर 2023 को एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें श्री कामेश्वर ठाकुर उप मुख्य अंकेक्षक सहयोग समितियां सह नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण एवं श्री दीपक कुमार सहायक निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना उपस्थित रहे इस बैठक में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ के विषय विशेषज्ञ श्री श्रीकुमार जोशी, से.नि. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता म.प्र. भोपाल, श्री के.आर. साहु, से.नि. महाप्रबंधक, अपेक्स बैंक भोपाल, श्री राजेन्द्र सक्सेना, मोटिवेशनल स्पीकर, डॉ. अतुल दुबे, प्रोफेसर, बी.एस.एस.एस, आई.ए.एस.कॉलेज श्री नवल किशोर तिवारी, पूर्व प्राचार्य, सहकारी प्रबंध संस्थान, पूणे, श्री यू.एस.ठाकुर, से.नि. उप सचिव, वित्त, श्री अंशुल अग्रवाल, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, श्री संजीव गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, श्रीमती सृष्टि उमेकर, अर्थशास्त्री, श्री अभय गोखले, से.नि. प्रबंधक, अपेक्स बैंक भोपाल, श्री पी.के. एस. परिहार, से.नि. प्रबंधक, अपेक्स बैंक भोपाल, श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, श्री जी.पी. मांझी, प्राचार्य, श्रीमती रेखा पिप्पल, व्याख्याता, श्रीमती मीनाक्षी बान, कम्प्यूटर व्याख्याता एवं अन्य विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहें। इस बैठक में विषय विषेषज्ञों एवं पटना से पधारे अधिकारी से विचार विमर्श कर 12 सप्ताह का प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करते हुए सहमति प्रदान की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन जी के द्वारा की गई। बैठक समापन पर संघ के महाप्रबंधक द्वारा सभी उपस्थित विषय विषेषज्ञों का आभार व्यक्त किया गया।

एक दिवसीय सेमीनार-कार्यशाला का आयोजन

भोपाल। कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की वृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के अन्तर्गत एक दिवसीय कार्यशाला मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल में दिनांक 29.08.2023 को जिला भोपाल के हस्तशिल्पियों हेतु आयोजित की गई। जिसमें 50 से भी अधिक महिलाओं प्रतिभागियों ने भाग लिया। सीएचसीडीएस परियोजना अन्तर्गत निम्नानुसार गतिविधियों से एक दिवसीय कार्यशाला को स्मरणीय बनाया गया।

श्री संतोष येड़े, राज्य समन्वयक सघं मुख्यालय म.प्र. द्वारा वृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) का परिचय कराया, साथ ही एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा एवं मंच संचालन किया गया। श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी सघं द्वारा अपने उदबोधन में सहकारिता के उद्देश्य तथा सिद्धांतों एवं लाभ से अवगत कराया जो किसी भी सहकारी संस्था, संगठन एवं समूह के संचालन हेतु अनिवार्य है। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रदेश के हस्तशिल्पियों हेतु आर्टीजन्स परिचय पत्र उपस्थित चिन्हित प्रतिभागियों को श्री ऋतुराज रंजन जी द्वारा वितरित किये गये। श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक म.प्र. राज्य सहकारी सघं द्वारा भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय से प्रायोजित म.प्र.सहकारिता नीति के अन्तर्गत सहकारी समिति के संचालन एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु अभिभाषण दिया गया। श्री मनीष राजपूत (सी.ई.ओ.) एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह राजपूत (सचिव) शीड संस्था भोपाल ने कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण योगदान दिया। श्रीमती मीनाक्षी बान कम्प्यूटर, व्याख्याता ने महिलाओं को कार्य के प्रति जागरूक कैसे रहे इस संबंध में बताया गया। श्री अंशुल अग्रवाल, सीए ने जीएसटी विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी साथ ही (जैम पोर्टल) वर्चुअल मेलो में ई–कामर्स प्लेटफार्म की भागीदारी, जी आई पंजीयन की प्रकिया, मुद्रा ऋण, हितग्राहियों को किस प्रकार मिलता है बताया। श्री तरूण वेदी, इ.डी.पी. एक्सपर्ट द्वारा विपणन कौशल, उद्यमशीलता कौशल, संचार, पैकेजिंग और ब्रांड प्रचार, गुणवत्ता अनुपालन, सुरक्षा उपाय, अपशिष्ट प्रबंधन, उत्पादन मूल्य निर्धारण के बारे में कैसे काम करते है समझया गया। श्री अर्चित सहारे, सहायक निदेशक (ह.) सीएचसीडीएस के उद्देश्यों की रूपरेखा, CHCDS योजना अंतगर्त प्रशिक्षण कार्यक्रमो, मेंलो, कौशल विकास की विस्तृत रूप से जानकारी दी। श्री अभिमन्यु टकियार, फैशन डिजाइनर, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा डिजाइन में वृद्वि के महत्व पर चर्चा, क्राफ्ट की जानकारी, मार्केटिंग कैसे करे बताया गया। प्रतिभागी श्रीमती नीतू यादव व सुश्री फिरोज जहॉ ने भी अपने विचार व्यक्त किये। श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, अवतार सिंह वैष्णव ने सेमीनार/कार्यशाला अवसर पर प्रतिभागियों का पंजीयन किया। श्री माखन सिंह शफीफ खान ने योजना हेतु निर्मित पुस्तक "वृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)" म.प्र. हस्तशिल्प क्लस्टरों के विकास हेतु सेमीनार/कार्यशाला अवसर पर प्रतिभागियों को वितरित की गई। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों का आभार श्रीमति श्रद्धा श्रीवास्तव, प्रशिक्षक ने व्यक्त किया गया।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित अमरपुरा में एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण वर्ग सम्पन्न

नौगांव। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव जिला छतरपुर के द्वारा दिनांक 15.09.2023 को प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित अमरपुरा विकास खण्ड विजावर में एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण वर्ग शिविर आयोजित किया जिसमें समिति के फड़ मुंशी श्री पंचमलाल अहिरवार, उप सरपंच श्री हरी सिंह यादव सदस्य श्री राम मिलन यादव, श्री कल्लू रजक, श्री गोकुल कुशवाहा, श्री तुलाराम अहिरवार, श्री प्रेम लाल प्रजापति इत्यादि वनोपज सदस्य आवश्यक रूप से उपस्थित रहे शिविर का संचालन बाबूलाल कुशवाहा जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव जिला छतरपुर म. प्र. ने किया। प्रशिक्षण अवसर पर प्रतिभागियों को विनाश विहीन विदोहन, वनोपज औषधियों की जानकारी, सहकारी लेखाकंन, बैठक निर्वाचन प्रक्रिया, सहकारी सिद्धांत, अधिनियम-नियम आदि के बारे में विस्तृकत जानकारी दी गई।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित वक्स्वाहा एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न

नौगांव। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव जिला छतरपुर के द्वारा दिनांक 18.09.2023 को प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित वक्स्वाहा विकास खण्ड बड़ामलहरा जिला छतरपुर मे एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण वर्ग शिविर का आयोजन किया गया,जिसमें सहकारिता का अर्थ, समिति के उद्देश्य, सदस्यों के अधिकार, लेखाकंन, बैठक की कार्यवाही विवरण, वनोपज संग्रहण, विनाश विहीन विदोहन, शासकीय जन-कल्याकणकारी योजना से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण में समिति अध्यक्ष श्री दशरथ अहिरवार, समिति प्रबंधक, श्री बाबूलाल अहिरवार फड़ मुंशी, श्री बद्री यादव, सदस्य श्री हरी शंकर अहिरवार, श्री कमलापत अहिरवार, श्री सन्तू यादव, श्री देशराज लोधी, महिला सदस्य श्रीमती सुमन अहिरवार, श्रीमती भूरीबाई सौंर, श्रीमती कमला अहिरवार एवं वनोपज समिति के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। शिविर का संचालन बाबूलाल कुशवाहा जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र ने किया।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित ग्राम सिलावट मे एक दिवसीय सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण आयोजित

नौगांव। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव जिला छतरपुर के द्वारा दिनांक 14.09.2023 को प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित ग्राम सिलावट विकास खण्ड विजावर जिला छतरपुर मे एक दिवसीय सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण वर्ग शिविर आयोजित किया गया जिसमें सहकारिता का अर्थ, समिति के उद्देश्य संचालक मंडल के कर्तव्य सहित कई अन्यप विषयों पर जानकारी बाबूलाल कुशवाहा जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव द्वारा दी गई जिसमें वन वीट प्रभारी एवं प्रभारी समिति प्रबंधक श्री लक्ष्मी नारायण सेंन, वन रक्षक श्री अवधेश कुमार सक्सेना, वनोपज समिति अध्यक्ष एवं फड़ मुंशी श्री भागवली पटेल, सदस्य श्री कन्हैया लाल पाल, श्री कन्छेदी कुशवाहा, श्री पुष्पेन्द्र पटेल, महिला सदस्य श्रीमती विद्या पटेल, श्रीमती हब्बी पटेल, श्रीमती बूंदाबादी पटेल इत्यादि वनोपज सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

पैक्स कम्प्यूटराईजेशन पर एक दिवसीय का आयोजन

इंदौर। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर के द्वारा दिनाँक 26/09/2023 को सेवा सहकारी संस्था - बड़ी कलमेर तहसील हातोद ज़िला इंदौर में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित गया। इस दौरान संस्था के प्रबंधक श्री राजेश जाधव, सेलशमेंन श्रीश्याम सिसोदिया , सदस्यगण, एवं किसान बंधु उपस्थित रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला प्रशिक्षक प्रदीप रैकवार द्वारा सहकारिता के महत्व, सिद्धांत, समिति लेखाकंन, समिति प्रबंधन, बैठक कार्यवाही विवरण, सहकारिता से समृद्धि, शासन की लोक कल्याण योजनाएं, बी पैक्स उपविधि पर जानकारी, पैक्स कम्प्यूटराइजेशन पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर संस्था के प्रबंधक श्री राजेश जाधव द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

जिला सहकारी संघ सीहोर की 38 वीं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

सीहोर। जिला सहकारी संघ मर्यादित सीहोर मे दिनांक 13-09-2023 दिन बुधवार को 38 वीं वार्षिक साधारण सभा जिला सहकारी संघ सीहोर कार्यालय भवन पर आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुधीर कैथवास, उपायुक्त सहकारिता जिला सीहोर, सुनील सक्सेना वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं प्रशासक जिला सहकारी संघ की अध्यक्षता में एवं पी. एन. यादव महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीहोर महेन्द्र सिंह पटेल पूर्व संचालक भोपाल दुग्ध सहकारी संघ, सौभाल सिंह ठाकुर संचालक जिला लघु वनोपज संघ सीहोर, कैलाश चन्द्रवंशी दुग्ध संस्था मुहाली, प्रदीप उपाध्याय संचालक कर्मचारी साख जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सीहोर के विशेष आतिथ्य में प्रारम्भ हुई।

सभी अतिथियों का स्वागत तेजसिंह ठाकुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पुष्पमाला से किया गया। साधारण सभा की अध्यक्षता करते हुए सुनील सक्सेना द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि सहकारिता आन्दोलन के प्रचार-प्रसार के लिए जिला सहकारी संघ एक जिला स्तरीय प्रतिनिधि संस्था है सभी सहकारी संस्थाऐं द्वारा जिला संघ को देय अभिदाय की राशि समय पर भुगतान करें जिससे जिला सहकारी संघ, सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित कर सके। सुधीर कैथवास उपायुक्त द्वारा कहा कि सहकारिता आन्दोलन के विकास हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा नई सहकारिता नीति बनाई गई है एवं पैक्स संस्थाओं की नई उपविधियाँ तैयार की गई हैं ताकि सहकारिता का लाभ संस्थाओं के माध्यम से जन-जन तक पहुंच सके। पी. एन. यादव महाप्रबंधक द्वारा कहा कि सहकारिता आन्दोलन का प्रचार प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला सहकारी संघ अपने उद्देशासार कर रहा है इसके लिए यहाँ के कर्मचारी बधाई के पात्र हैं एवं बैंक सहकारिता की भावना अनुरूप हमेशा आपके कार्य में सहयोग करता रहेगा। इस अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल के प्रतिनिधि गणेश मांझी प्राचार्य, अरूण कुमार जोशी, पूर्व प्राचार्य, धनराज सैंदाणे लिपिक, धनराज लेखापाल, जगदीश चन्द्रवंशी, सुन्दरलाल जैन तथा अन्य संस्थाओं से पधारे प्रतिनिधिगण से उपस्थित रहे। तेजसिंह ठाकुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा साधारण सभा के विषय एवं निर्णय पढ़कर सुनाए गए जिन्हें उपस्थित सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। अन्त में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सभा समाप्ति की घोषणा की गई।

राजीव मछुआ समिति में सहकारी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

जबलपुर, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर के जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक पीयूष राय व्दारा एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन राजीव मछुआ सहकारी समिति मर्यादित झिरिया जिला कटनी मे किया गया। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष श्री धनीराम बर्मन तथा समिति के सदस्य श्री सूरज बर्मन, श्री चन्द्रभान बर्मन, श्रीमती अजी बाई, श्री कृष्ण कुमार आदि।। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षक पीयूष राय ने सभी उपस्थित सदस्यों को आमसभा की बैठको तथा बैठको की कार्यवाही, सहकारिता के सिद्धांत, समिति गठन की प्रक्रिया, बैठक कार्यवाही विवरण, समिति को बहुउद्देश्यी कैसे बनाये, बी-पैक्स् उपविधियां इत्यारदि की जानकारी प्रदान की गई। श्री बर्मन ने आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को समाप्त किया।

मांझी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित भैसवाही, प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

जबलपुर, सहकारी प्रशिक्षण केंन्द्र जबलपुर द्वारा मांझी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित भैसवाही जिला कटनी (म.प्र.) में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक पीयूष राय द्वारा किया गया। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष श्री रामदयाल बर्मन उपाध्यक्ष श्री रामनाथ बर्मन, सदस्यो मे श्री चुन्नु बर्मन, श्री विशाल बर्मन तथा समिति के अन्य सदस्यो ने प्रशिक्षण मे भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षार्थियो को सहकारिता के सिद्धान्त तथा आम सभा की बैठको और नए क्षेत्रों मे समितियों के गठन हेतु चर्चा करते हुये प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलता पूर्वक पूरा किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में समिति के सदस्यों ने बडी संख्या में प्रशिक्षण लिया। कार्यक्रम के अन्त मे समिति के अध्यक्ष श्री रामदयाल बर्मन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि, सहकारिता ही ऐसा माध्यम है जिसे गांव के ग्रामीण जनो तक पहुचा जा सकता है एवं सहकारिता से आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।

हस्तशिल्प कारीगरों हेतु कार्यशाला का आयोजन

बालाघाट। वृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के अंतर्गत एक दिवसीय सेमिनार/कार्यशाला का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के द्वारा जिला बालाघाट (म.प्र.) में किया गया।

यह कार्यक्रम कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा प्रायोजित था। इस कार्यक्रम मे कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप मे श्री अर्चीत सहारे (ए.डी.), विशेषज्ञ संस्था् सीड के श्री धर्मेन्द्र सिंह राजपूत (सचिव), सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर से श्री पीयूष राय (पर्यवेक्षक), उद्यमिता विषय विशेषज्ञ श्री धर्मेन्द्र मिश्रा (सेक्रेटरी), एम.एस.एम.ई. से श्री राकेश नेवारे (जिला समन्वयक) आदि गणमान्य जन उपस्थित रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम मे लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

श्री पीयूष राय ने सहकारिता के महत्व, समिति के लाभ तथा समिति गठन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार पूवर्क जानकारी प्रदान की गई। श्री धर्मेन्द्र मिश्रा ने हस्तशिल्प में कौशल विकसित करने, रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने, गरीब ग्रामीणों की आजीविका को बढावा देने, हस्तशिल्प को उद्योग से किस प्रकार जोड़ा जाए जिससे व्यक्तिगत आय मे वृध्दि हो सके इस विषय मे मार्गदर्शन प्रदान किया। श्री राकेश नेवारे, मास्टर क्राफ्ट पर्सन/डिजाईनर ने बांस एवं कढ़ाई के उत्पाद तैयार करने एवं तकनीकी जानकारी, मशीन उपकरणों इत्यादि पर जानकारी प्रदान की गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम मे प्रशिक्षणार्थियों को श्री धर्मेंद्र सिंह राजपूत द्वारा जी.एस.टी./जैम पोर्टल तथा बैंक, मुद्रा ऋण विषयों पर जानकारी प्रदान की गई। श्री अर्चीत सहारे (ए.डी.) ने सीएचसीडीएस योजना के बारे मे विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।

हस्तशिल्प कारीगरों हेतु उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन

बालाघाट। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की परियोजना वृहद हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन दिनांक 23 सितम्बर, 2023 से 28 सितम्बर, 2023 तक बालाघाट (म.प्र.) में किया गया। उक्त कार्यक्रम मे कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री अर्चित सहारे (ए.डी.), सीड संस्था के श्री धर्मेन्द्र सिंह राजपूत (सचिव), सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के जिला सहकारी प्रशिक्षक एवं पर्यवेक्षक श्री पीयूष राय, श्री धर्मेन्द्र मिश्रा (सचिव), एम.एस.एम.ई. से श्री राकेश नेवारे (जिला समन्वेयक) उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम मे 20 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। श्री धर्मेन्द्र सिंह राजपूत जी ने

प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि, उद्यमिता, उद्यमियों की भूमिका, उद्यम के प्रकार, आवश्यक दस्तावेज, उद्यम स्थापित करने हेतु प्रक्रिया एवं उपलब्ध सुविधाएं जोखिम कारक और उद्यमी व्यवहार, विपणन, निर्यात, पैकेजिंग एवं प्रचार, संचार कौशल, डिजाइन, गुणवत्ता अनुपालन, व्यापार मूल्य निर्धारण, ग्राहक व्यवहार, खुदरा स्टोर, पर मौलिक ज्ञान, मार्केटिंग की जानकारी, मुद्रालोन की जानकारी, विपणन, निर्यात, पैकेजिंग एवं प्रचार, संचार कौशल, डिजाइन, व्यापार, मूल्य निर्धारण। वित्तीय पहलुओं, उद्यमिता विकास से संबंधित कई अन्य जानकारी एवं श्री पियूष राय द्वारा सहकारी समिति के गठन, सहकारिता के उद्देश्य, सिद्धांत पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

पेड़ हमें देते हैं सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखें- प्रशिक्षक एच. के. राय

नौगांव। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव द्वारा प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित धवाड़ जिला छतरपुर में एक दिवसीय वर्ग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम शुभारंभ बीट प्रभारी श्री गौरव खरे,वन रक्षक ने मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया, समिति के अध्यक्ष श्री दशरथ यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथियों एवं सदस्यों का स्वागत वंदन किया। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव के जिला सहकारी प्रशिक्षक एच.के. राय ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सदस्यों को बताया की वृक्ष हमारे लिए बहुत महत्वहपूर्ण है हमें सभी को बैठकर सोचना चाहिए कि, वृक्ष हमारे लिए पूरे जीवनकाल हमें में कुछ ना कुछ देते रहते हैं जैसे फूल, फल, जलाऊ लकड़ी, शीतल छाया, और सबसे बड़ी बात हमें प्राण वायु भी हमारे वृक्षों के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। प्रशिक्षक ने प्रशिक्षण के दौरान सभी सदस्यों को शपथ लेने का आग्रह किया कि हम सभी हर वर्ष एक-एक पेड़ लगाएंगे और उस पेड़ की तब तक सेवा करेंगे जब तक की वह आत्मनिर्भर न हो जाए, और दृढ़ संकल्प ले कि कभी भी हम हरे पेड़ को नहीं काटेंगे क्योंकि वनो के बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। श्री राय के द्वारा संचालक मंडल के अधिकार और कर्तव्यों, सिद्धांत, समितियों के गठन की प्रक्रिया, बैठक कार्यवाही विवरण, लोक कल्याणकारी शासन की योजना पर जानकारिया प्रदान की गई।

फसलों के नुकसान का सर्वे कराकर दी जाएगी राहत राशि- मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कमिश्नर्स-कलेक्टर्स को किया संबोधित

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पूरे प्रदेश में लगभग अच्छी वर्षा हो रही है। वर्षा की कमी समाप्ति की ओर है। महाकाल भगवान को अच्छी वर्षा के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही अतिवृष्टि से सतर्क रहना होगा। फसलों को थोड़ा नुकसान हुआ है। आकलन करके सर्वे कराया जाए। आरबीसी 6-4 के अंतर्गत तहत किसानों को राहत की राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री कार्यालय के सभागार से वीसी के माध्यम से प्रदेश के कलेक्टर्स-कमिश्नर्स को संबोधित किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मलय श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री शिवशेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री उमाकांत उमराव तथा जिलों के कलेक्टर्स-कमिश्नर्स वर्चुअली शामिल हुए।

लाड़ली बहना आवास योजना के लिए होगा पंजीयन

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गई लाड़ली बहनों को आवास स्वीकृत किया जायेगा। इसके लिए लाड़ली बहनों का पंजीयन होगा। योजना से संबंधित फॉर्म जनपद पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये जायेंगे। दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित करके जमा करना होगा। इस योजना का 17 सितम्बर को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से शुभारंभ किया जायेगा।

एकात्मता की प्रतिमा अद्भुत प्रकल्प

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर अद्भुत काम हो रहा है। ओंकारेश्वर में आदि गुरू शंकराचार्य की एकात्मता की प्रतिमा का अनावरण होगा। आदि गुरू शंकराचार्य ने भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम किया। एकात्मता की प्रतिमा अद्भुत प्रकल्प है जो दुनिया को सारे द्वन्दों से बचाएगी। युद्ध नहीं शांति, घृणा नहीं प्रेम इसका संदेश अद्वेत वेदांत ही देगा। आगामी 18 सितम्बर को ओंकारेश्वर में भव्य कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम सुबह 10.30 बजे से लाइव दिखाया जायेगा। हर प्रमुख मंदिर में लाइव कार्यक्रम दिखाने की व्यवस्था की जाए। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सभी पंथों, अखाड़ों के संत ओंकारेश्वर आ रहे हैं।

लाड़ली बहनों को रसोई गैस सिलेंडर 450 रूपये में मिलेगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों के प्रचार रथ चल रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर लोगों को उपलब्धियों की जानकारी दी जाए। लाड़ली बहनों को रसोई गैस सिलेंडर 450 रूपये में मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की बहनों को इसका लाभ मिलेगा। सिलेंडर रिफलिंग योजना का पंजीयन पोर्टल पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की तरह इस योजना का भी पंजीयन का कार्य करने के लिए केंद्र बनाये जायें। इसकी सूची 25 सितम्बर को अद्यतन की जायेगी। पंजीयन ऑनलाइन और जरूरत पड़ने पर ऑफलाइन किया जाएगा। बहनों को सिलेंडर रिफलिंग की अंतर की राशि रिफंड की जायेगी।

(पृष्ठ 1 का शेष)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश में .....

उन्होंने कहा कि इसके कारण कोऑपरेटिव के कई उत्कृष्ट मॉडल इस देश में सामने आए और विशेषकर ग्रामीण विकास और कृषि विकास का एक बहुत बड़ा माध्यम सहकारिता क्षेत्र बना। उन्होंने कहा कि 1960, विशेषकर 1967, के बाद सहकारिता क्षेत्र में राजनीतिक दखल बढ़ने लगा और धीरे-धीरे देश के अर्थतंत्र में भी गिरावट आई और इसके कारण सहकारिता आंदोलन को बहुत क्षति पहुंची।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज सहकार के उत्कृष्ट मॉडल अमूल के तहत देश में 36 लाख बहनें 60,000 करोड़ रूपए का दूध का व्यापार करती हैं और इनमें से एक भी बहन की पूंजी 100 रूपए से अधिक नहीं लगी है। उन्होंने कहा कि गुजरात, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र, की समृद्धि में कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मॉडल हमारे देश के लिए बहुत उपयुक्त है क्योंकि हमें आर्थिक विकास के साथ-साथ रोजगार, mass production और production by masses भी चाहिए। उन्होंने कहा कि mass production से देश के अर्थतंत्र को गति मिलेगी और production by masses से देश के हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा । श्री शाह ने कहा कि देश के अर्थतंत्र से जुड़ी संस्थाओं के साथ सहकारिता क्षेत्र का बेहतरीन संयोजन ही भारत को आगे बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता का मॉडल मानवता-केन्द्रित मॉडल है। आज देश में 30 करोड़ सदस्यों के साथ साढ़े 8 लाख कोऑपरेटिव समितियां हैं, 93,000 पैक्स (PACS) हैं, 2 लाख दुग्ध समितियां हैं और इफ्को, कृभको, अमूल जैसी कई विश्वप्रसिद्ध सहकारी संस्थाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत के 12 कोऑपरेटिव बैंकों को विश्व की 300 प्रथम वरीयता प्राप्त कोऑपरेटिव समितियों में स्थान प्राप्त है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश में अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन कर कोऑपरेटिव आंदोलन में एक नई जान डालने और इसे फिर से गति देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से 2023 तक देश के उन 60 करोड़ लोगों, जो देश के अर्थतंत्र का हिस्सा ही नहीं थे, को बैंक अकाउंट, घर, पीने का पानी, बिजली, गैस कनेक्शन, शौचालय और 5 लाख रूपए तक का स्वास्थ्य का खर्चा दिया, जिससे इन 60 करोड़ लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। श्री शाह ने कहा कि ये 60 करोड़ लोग अब देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़ चुके हैं और देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन इनके पास अपनी पूंजी नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल सहकारिता के माध्यम से ही इन 60 करोड़ लोगों को देश के विकास के साथ जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें छोटी पूंजी वाले हज़ारों लोग मिलकर बड़ी पूंजी वाले उद्योगों के साथ स्पर्धा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन 60 करोड़ लोगों को देश के विकास में योगदान देने, Women-led Development को आगे बढ़ाने, ग्रामीण विकास को महत्व देकर गांवों से शहरों की ओर पलायन रोकने और हर व्यक्ति को देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने के लिए सहकारिता के सिवा कोई और मॉडल हो ही नहीं सकता।

श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए भी कई काम किए हैं, जैसे, सेटलमेंट के प्रॉब्लम को रिजर्व बैंक के साथ उठाया और अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी सेटलमेंट करने का अधिकार दे दिया गया है। इसके साथ ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अब नई शाखाएं भी खोल सकेंगे, बैंक मित्र भी बना पाएंगे, माइक्रो एटीएम भी खोल पाएंगे और रेजिडेंशियल लोन देने की इनकी ऋण सीमा को भी दोगुना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में ग्रामीण क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने निर्णय लिया है कि आने वाले 5 सालों में 3 लाख नए पैक्स बनाएंगे और हर पंचायत में एक पैक्स होगा और यह पैक्स मल्टीडाइमेंशनल होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 20 प्रकार की नई गतिविधियों को पैक्स के साथ जोड़कर इन्हें वायबल बना दिया है। श्री शाह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने मॉडल बायलॉज बनाकर सभी राज्यों को भेजे और देश के 23 राज्यों ने इन मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रीने कहा कि मोदी सरकार ने मल्टीस्टेट ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जो देशभर में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीदने और विश्व के बाजार में बेचने की व्यवस्था करेगी। एक मल्टीस्टेट एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव भी बनाई, जो किसानों के उत्पादों को एक्सपोर्ट करेगा और इसका पूरा मुनाफा सीधा किसान के पास जाएगा। इसके अलावा एक मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव बीज समिति के लिए भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना भी पैक्स के माध्यम से आगे चलाई जाएगी। इसके साथ-साथ सहकारिता यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है, GEM के माध्यम से सारे कोऑपरेटिव के उत्पादों को बेचने की भी व्यवस्था की गई है और 1100 नए एफपीओ भी पैक्स के माध्यम से बनेंगे। उन्होंने कहा कि पैक्स अब CSC का भी कम कर सकेंगे।

श्री अमित शाह ने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने कई सरकारी बदलाव भी किए हैं। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में कोऑपरेटिव और कॉर्पोरेट, दोनों को एकसमान स्तर पर लाने का काम आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव की गतिविधियों को अगर हम समयानुसार अत्याधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर आगे बढ़ाएं, तो भारत जैसे देश में रोजगार के साथ अर्थतंत्र के विकास का इससे बड़ा और अच्छा तरीका और कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आने वाले दिनों में सहकारिता क्षेत्र में कई नए कदम उठाने जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा मानकर मत चलिए कि कोऑपरेटिव अप्रासंगिक हो चुका है, बल्कि कोऑपरेटिव का भविष्य और उज्ज्वल होने जा रहा है।

मत्स्य-उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिये म.प्र. सरकार बधाई की पात्र : केन्द्रीय मंत्री

मछुआरा समाज के विकास के लिये म.प्र. सरकार संकल्पित : मछुआ कल्याण मंत्री श्री सिलावट

भोपाल : केन्द्रीय मत्स्य-पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री पुरूषोत्तम रूपाला ने कहा है कि गत 3 वर्षों में मध्यप्रदेश में मत्स्य-उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई है। प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य-संपदा योजना और मछुआरा क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से मत्स्य-उत्पादन बढ़ा है और मछुआरों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। श्री रूपाला ने इसके लिये मध्यप्रदेश सरकार को बधाई दी।

केन्द्रीय मंत्री श्री रूपाला ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा भोपाल में 25 करोड़ रूपये की लागत से एक्वा पार्क के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। पार्क में अनुसंधान केन्द्र, प्र-संस्करण सुविधा, जल पर्यटन, सजावटी मत्स्य-पालन जैसी सुविधाएँ होंगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तटीय मत्स्य-पालन अधिनियम (कोस्टल एक्वाकल्चर एक्ट) के संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। भारत को अपनी वैश्विक रैंकिंग को बनाये रखने के लिये झींगा पालन को बढ़ावा देना चाहिए।

प्रधानमंत्री मत्स्य-संपदा योजना के देश में क्रियान्वयन के सफल 3 वर्ष पूरे होने पर आज ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ केन्द्रीय मंत्री श्री पुरूषोत्तम रूपाला और प्रदेश के जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने किया। केन्द्रीय मत्स्य-पालन राज्य मंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान एवं डॉ. एल. मुरूगन, अध्यक्ष मध्यप्रदेश मत्स्य कल्याण बोर्ड श्री सीताराम बाथम, अरूणाचल प्रदेश के कृषि बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य-पालन मंत्री श्री तागे ताकी और सांसद श्री शंकर लालवानी उपस्थित थे।

जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने कहा कि देश और प्रदेश के विकास में मछुआ समुदाय का योगदान सराहनीय है। मछुआ समुदाय का चहुँमुखी विकास जरूरी है और मध्यप्रदेश सरकार इसके लिये संकल्पित और प्रतिबद्ध है। प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सफल क्रियान्वयन से गत 3 वर्षों में मछुआ समाज के कल्याण और मत्स्य-पालन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है।

239 नई परियोजनाएँ स्वीकृत

केन्द्रीय मंत्री श्री रूपाला ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिये पीएमएमएसवाय में 103 करोड़ 11 लाख रूपये लागत की 239 नयी मत्स्य-पालन परियोजनाएँ स्वीकृत की हैं। इन परियोजनाओं में झींगा पालन, मोती पालन, केज कल्चर, कोल्ड स्टोरेज आदि के क्षेत्र में कार्य होगा।

श्री रूपाला ने कार्यक्रम स्थल पर मत्स्य पालन प्रदर्शनी का शुभारंभ और भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रगति यात्रा संबंधी पुस्तक का विमोचन भी किया। प्रदर्शनी स्टॉलों में भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय मत्स्य पालन पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय मत्स्य-पालन संस्थान और नॉटिकल इंजीनियरिंग संस्थान की गतिविधियों के साथ-साथ विभिन्न उद्यमियों द्वारा बेचे जा रहे जाल, चारा, मूल्य वर्धित उत्पादों आदि को प्रदर्शित किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)
(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का संगठन)
NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL EXTENSION MANAGEMENT
(An Organization of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Govt. of India)

Nodal Training Institute (NTI)
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल
(M.P. State Cooperative Union Ltd. Bhopal)
E-8/77 Trilanga Road, Shahpura Bhopal -462039

Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers (DAESI)
डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स (देसी)
"इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा" (देसी)
शीघ्र आयें प्रवेश पायें

उद्देश्य : इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चरल इनपुट्स डीलर्स को पैरा–एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स में बदलना है। जिससे एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सिस्टम को मजबूत किया जा सके। इससे इनपुट डीलर्स को किसानों की बेहतर सेवा करने में मदद मिलेगी जिससे :–

- इनपुट के कुशल संचालन में इनपुट डीलरों की क्षमता का निर्माण।
- कृषि आदानों के विनियमन को नियंत्रित करने वाले कानूनों के बारे में ज्ञान प्रदान करना।
- किसानों के लिए इनपुट डीलरों को ग्रामीण स्तर पर कृषि संबंधी जानकारी का एक प्रभावी स्त्रोत (वन स्टॉप शॉप) बनाना।
- ग्रामीण रोजगारोन्मुखी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिये ग्रामीण स्तर पर बीज, खाद, कीटनाशक या दवाई की दुकान के लाइसेंस की आवश्यकता होती है। वर्तमान में लाइसेंस लेने के लिए युवक–युवतियों को परेशानी न हो इसके लिए राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल, आत्मा एवं म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल के सहयोग से देसी कोर्स की शुरूआत की गयी है।

एग्रीकल्चर में डिप्लोमा कोर्स क्यों करें?

- एग्रीकल्चरल डिप्लोमा एग्रीकल्चर या जैविक प्रक्रिया से संबंधित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीकी स्तर पर मानव संसाधन का विकास कर एग्रीकल्चर उद्योग की प्रगति करना है।
- इस कोर्स में किसी भी एग्रीकल्चर उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के कौशल को बढ़ाया जाता है।
- एग्रीकल्चर में डिप्लोमा कोर्स के साथ छात्र 10वीं के बाद से ही अपने प्रारंभिक करियर की शुरुआत कर सकते हैं।
- इस कोर्स के जरिए एग्रीकल्चर उद्योग में आवश्यक कौशल सीखने से अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने में मदद मिलेगी क्योंकि गुणवत्ता वाले उत्पादों की मांग अधिक है।
- कृषि डिप्लोमा कोर्स छात्रों के सामने करियर के विभिन्न अवसर खोलता है। बड़ी–बड़ी नामी कम्पनियां जैसे–ITC, Britannia, Godrej आदि डिप्लोमा छात्रों को इंटर्नशिप भी ऑफर करती हैं।

इन विषयों पर मिलेगा प्रशिक्षण :–

सैद्धांतिक प्रशिक्षण के अंतर्गतः–

क्र	विषय
1.	मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन।
2	वर्षा आधारित खेती।
3.	बीज एवं बीज उत्पादन।
4	सिंचाई तकनीक एवं उनका प्रबंधन।
5	खरपतवार प्रबंधन।
6	कृषि उपकरण और मशीनरी की जानकारी।
7	कृषि में कीट एवं रोग नियंत्रण।
8	प्रमुख स्थानीय फसलों की फसल उत्पादन तकनीक।
9	कृषि आदानों से संबंधित अधिनियम, नियम एवं विनियम।
10	कृषि क्षेत्र से संबंधित शासन की विभिन्न योजनाएं एवं कृषि प्रसार तकनीक।
11	विस्तार दृष्टिकोण और तरीके।
12	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
13	फसल बीमा योजना।
14	बीज, कीट व मण्डी अधिनियम।
15	उर्वरक अधिनियम।

व्यावहारिक प्रशिक्षण के अंतर्गतः– व्यावहारिक प्रशिक्षण वर्ग के अंतर्गत कृषि से संबंधित संस्थान जैसे – कृषि विज्ञान केन्द्र, मृदा जांच प्रयोगशाला, कृषि महाविद्यालय/ कृषि विश्वविद्यालय, उद्यानकीय महाविद्यालय, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं प्रगतिशील किसानों के प्रक्षेत्र पर प्रशिक्षणार्थियों को एक्सपोजर विजिट कराया जावेगा।

अवधि – 01 वर्ष

यह कार्यक्रम 48 सप्ताह की अवधि का है जिसमें 40 कक्षा सत्र एवं 08 फील्ड विजिट है।

यह कोर्स सप्ताह में एक दिन (सरकारी अवकाश के दिन) आयोजित किया जाता है।

पाठ्यक्रम शुल्क–

देसी डी.डी. : "Diploma In Agriculture Extension Services For Input Dealers, Bhopal" के नाम की डी.डी. राशि रु. राशि रू. 20,000/–

शैक्षणिक योग्यता–10 वीं उत्तीर्ण से लेकर डिग्रीधारक तक।

कुल सीट – 40

आवश्यक दस्तावेज

- 10 वी उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र
- 12वी उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र
- स्नातक उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र
- स्नातकोत्तर उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- दो पासपोर्ट साईज फोटो
- वैध लाईसेंस की प्रति (यदि आप कृषि इनपुट डीलर के रूप में काम कर रहे हैं)

कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए संपर्क सूत्र–

07554034839, 9826821281, 9826876158, 8770995805
Website- www.mpscu.in, www.mpscuonline.in
Email : rajyasangh@yahoo.co.in

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ की आमसभा सम्पन्न

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ की 52 वीं वार्षिक साधारण सभा संघ मुख्यालय में प्राधिकृत अधिकारी श्री आलोक कुमार सिंह, आई.ए.एस. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें म.प्र. की अध्यक्षता में दिनांक 18 सितम्बर 2023 को आयोजित की गई। इस अवसर पर श्री अरूणसिंह तोमर, भू.पू. अध्यक्ष, राज्य संघ, श्री अरविन्द मिश्रा, प्रतिनिधि, अन्नपूर्णा साख सहकारी संस्था, इंदौर श्री ए.के. सिंह, प्रबंध संचालक, बीज उत्पादक सहकारी संघ, भोपाल, श्री यतीश त्रिपाठी, सचिव, म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल, श्री के.के. द्विवेदी, सचिव, श्री संजय मौर्य, प्रबंधक, द्वय म.प्र. राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ, भोपाल, श्री योगेश पाण्डे, प्रतिनिधि, जिला सहकारी संघ पन्ना, श्री दामोदर वेलवासे, प्रतिनिधि अपेक्स बैंक कर्म. सह. साख संस्था, भोपाल, श्री ज्योतिलाल सोनी, प्रतिनिधि शी. सह. संघ कर्म. सह. साख संस्था, भोपाल, श्री बृजेश चौहान, से.नि. वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, तथा अन्य उपस्थित हुए।

प्राधिकृत अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ व्दारा बताया गया कि संघ द्वारा अपने सीमित संसाधनों एवं न्यूनतम मानव संसाधन के साथ वर्ष 2022–23 में अपने उद्देश्यों के अनुरूप विभिन्न विषयक प्रशिक्षण एवं नवाचार किए जाने के प्रयास किये गये हैं–

वर्ष 2022–23 के महत्वपूर्ण कार्य

1. सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन, शिक्षा प्रशिक्षण योजना अंतर्गत 20913 को प्रशिक्षण प्रदाय।
2. पैक्स/विपणन सहकारी संस्थाओं के समर्थन मूल्य की खरीदी एवं अर्बीटेशन प्रकरण तैयार करने, सहकारी समितियों के ऑनलाइन पंजीयन, अंकेक्षण के संबंध में मास्टर ट्रेनर तैयार करने, नवीन एवं गैर परम्परागत क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के गठन प्रक्रिया, लीकेज (हानि) की रोकथाम, कार्यालयीन कार्य निष्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण आदि विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित।
3. सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम आनलाइन (एच.डी.सी.एम) 20 सप्ताह के दो सत्र, कम्प्यूटर संबंधी पी.जी.डी.सी.ए एवं डी.सी.ए पाठ्यक्रमों का संचालन
4. नवीन एवं गैर परम्परागत क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के पंजीयन'' विषय पर प्रमुख सचिव सहकारिता के नेतृत्व में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
5. मध्यप्रदेश में कार्यरत सहकारी संस्थाओं में से उत्कृष्ट कार्य करने वाली 51 सहकारी संस्थाओं की सफलता की कहानियों पर आधारित पुस्तक, सहकारी परिपत्रों का संकलन (दो खण्डों में) एवं सहकारी निर्वाचन मार्गदशिका 2022, पैक्स कार्य मैन्यूअल जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का प्रकाशन।
6. सहकारी संस्थाओं एवं अन्य विभागों को आउटसोर्स के रूप में दक्ष एवं तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत एजेंसी के रूप में 1050 मानव संसाधन उपलब्ध कराए गए।
7. जबलपुर भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया तथा नौगांव प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण कार्य प्रारंभ।
8. प्रमुख सचिव सहकारिता एवं आयुक्त सहकारिता के मार्गदर्शन में नये क्षेत्रों में सहकारिता के विस्तार के लक्ष्य अनुसार संघ व्दारा हस्तशिल्प क्षेत्र में कारीगरों को सहकारिता के आधार पर संगठित कर उनके कौशल उन्नयन एवं आय संवर्धन हेतु विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय नई दिल्ली को प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर CHCDS परियोजना की स्वीकृति प्राप्त की गई।
9. मैनेज, हैदराबाद व कृषि विभाग के सहयोग से इनपुट डीलरों के कौशल संवर्धन हेतु DAESI प्रोजेक्ट अंतर्गत प्रशिक्षणों के लिए संघ का चयन नोडल एजेंसी के रूप में किया गया है।
10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के कौशल उन्नयन एवं आय संवर्धन हेतु च्ड दक्ष योजना के संचालन हेतु भारत सरकार सामाजिक न्याय विभाग व्दारा संघ को मान्यता प्रदान की गई है।
11. भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय की अपेक्षा अनुरूप पैक्स की आदर्श उपविधियों का अनुकूलन एवं क्रियान्वयन में सहकारिता विभाग, म.प्र. शासन को सहयोग प्रदान किया गया।

वर्ष 2023–24 के प्रस्तावित कार्यक्रम

1. शिक्षा प्रशिक्षण की योजना अंतर्गत 50900 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित। एच.डी.सी.एम. आनलाईन तथा च्ळक्ब ए क्ब। प्रशिक्षण के सत्रों का संचालन।
2. प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के कार्य मैन्युअल का विमोचन। नवीन क्षेत्रों में सहकारी समितियां बनाए जाने हेतु कार्यशाला का आयोजन एवं उनकी उपविधियों का निर्माण करना।
3. राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय सेमीनार तथा महिला एवं अन्य सहकारी संस्थाओं के संचालकों हेतु 3–3 दिवस के नेतृत्व विकास प्रशिक्षण का आयोजन।
4. सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर हेतु जबलपुर के कंटगा में स्थित स्वयं की भूमि पर म.प्र. गृह निर्माण मण्डल के माध्यम से भवन निर्माण पूर्ण कर लोकार्पण का आयोजन प्रस्तावित।
5. सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव में म.प्र.गृह निर्माण मण्डल के माध्यम से कार्यालय, अध्ययन कक्ष, बाउन्ड्रीवाल का निर्माण प्रारंभ।
6. सहकारी संस्थाओं एवं अन्य विभागों को आउटसोर्स के रूप में दक्ष एवं तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत एजेंसी के रूप में अधिकाधिक मानव संसाधन उपलब्ध कराना।
7. भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) नई दिल्ली के द्वारा वृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS) अंतर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन।
8. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का संगठन राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) हैदराबाद द्वारा देसी डिप्लोमा कार्यक्रम (Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers -DAESI) का संचालन।
9. PM दक्ष योजनान्तर्गत प्राप्त स्वीकृति अनुसार प्रशिक्षणों का आयोजन।
10. नये क्षेत्रों में सहकारिता के विस्तार हेतु नये सेक्टरों से संबंधित आदर्श उपविधियों का निर्माण।
11. पैक्स कम्प्यूटराईजेशन हेतु BIRD (NABARD) व्दारा निर्मित माड्यूल पर 5000 पैक्स कर्मियों के प्रथम चरण का प्रशिक्षण पूर्ण।

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल

ई-8/77 शाहपुरा त्रिलंगा भोपाल-462039,
फोन-0755-2926160, 2926159
E-mail: rajyasanghbpl@yahoo.co.in
mpscu.bpl@mp.gov.in

क्रमांक/भवन/2023/513/01 भोपाल दिनांक 18.09.2023

निविदा विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा सीएफसी भवनों का निर्माण क्रमशः भोपाल, इंदौर एवं नौगांव, जिला छतरपुर एवं संघ छात्रावास भवन, भोपाल में रिपेयरिंग एवं रिनोवेशन कार्य कराया जाना है, इस हेतु आनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा कमांक/513/भवन/2023 दिनांक 18.09.2023 अनुसार दिनांक 18.09.23 समय संध्या 6.00 से दिनांक 03.10.2023 समय दोपहर 3.30 बजे तक भरी जा सकती है। संपूर्ण विवरण हेतु म.प्र. शासन की वेबसाइट–www.mptendars.gov.in पर देखा जा सकता है।

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।